राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 29 अप्रैल 2026
वर्ष 14, अंक 20, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

तहसील परिसर में खराब पड़ा आरओ प्लांट, भीषण गर्मी में पेयजल संकट..03

पंजाब किंग्स के खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़..04

महिलाओं के आरक्षण के अधिकार को लागू कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और द्रमुक समेत विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को रोकने के लिए हमला बोला। मोदी ने कहा कि वह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महिलाओं के आरक्षण के अधिकार को लागू कराने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पीएम

संसद में इस विधेयक के गिरने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 'जन-आक्रोश महिला सम्मेलन' को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ''आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों-बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं।'' उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि ''काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। यह बड़ा लक्ष?य लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है।

विपक्षी दलों पर साधा निशाना

महिलाओं को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि ''हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा जैसी दिव्य शक्तियों की भूमि है, ऐसे में आप सभी बहन बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया।'' उन्होंने विपक्षी दलों खासतौर से सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ''अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा यह प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया लेकिन आप सभी बहनों को फिर से भरोसा दिलाता हूं कि आपके लिए आरक्षण लागू कराने में मैं कोई कोर-कसर नहीं छोड़ूंगा।

महिलाओं के साथ विपक्ष ने किया विश्वासघात

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी और द्रमुक जैसी 'परिवारवादी पार्टियों' ने एक बार फिर 'महिलाओं के साथ विश्वासघात' किया है। उन्होंने दोहराया कि 'ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि बेटियां विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचें और इन दलों ने पिछले 40 सालों से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगा रखा है।'' कभी महिलाओं से भोजपुरी तो कभी हिंदी में संवाद करते हुए मोदी ने कहा, ''साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती, समाज और देश मजबूत होता।'' उन्होंने कहा कि अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है और काशी की बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं।

भोजपुरी में पीएम मोदी ने किया संवाद

मोदी ने कहा, ''बेटियों को कई तरह के सवालों से गुजरना पड़ता था। उन्होंने पूर्वांचल में बोली जाने वाली भोजपुरी में किये जाने वाले संवादों को दोहराते हुए कहा ''लोग अतीत में महिलाओं से कहते ''तू का करबू'' ''तुहे का जरूरत ह'', ''ई काम तोहसे ना हो पाई।'' मोदी ने कहा कि कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था।

गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया

मोदी ने कहा, ''जब 25 साल पहले मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। इसके तहत स्कूल में बच्चियों का प्रवेश सुनिश्चित किया और 'मुख्यमंत्री कन्या कैलोरी निधि' जैसी पहल शुरू की ताकि फीस में मदद की जा सके।'' इस मौके पर उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप्र के भाजपा अध्यक्ष व केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

महिलाओं ने देवी का मुखौटा भेंट किया

जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने संसद का चित्र भेंट कर स्वागत किया। महिलाओं ने काशी की कला संस्कृति का प्रतीक देवी का मुखौटा भेंट किया। वाराणसी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नये संसद भवन के चित्र की जरदोजी की कढ़ाई भेंट की। मोर की प्रतिमा भी महिलाओं ने उन्हें भेंट की। महिला चिकित्सकों ने उन्हें पंचमुखी गणेश की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री को नमो घाट की स्मृति देकर शिक्षित समाज की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। इस आयोजन की विशेषता रही कि इसकी पूरी कमान महिलाओं ने संभाली। यहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था में महिला पुलिसकर्मी तैनात की गईं। सम्मेलन में महिला सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और समान अवसर जैसे मुद्दों पर मोदी ने संवाद किया।

यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनितों को CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थियों के खिले चेहरे

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 936 प्रधान परिचालक एवं प्रधान परिचालक (यांत्रिक) अभ्यर्थियों चेहरे नियुक्ति पत्र पाकर खुशी से खिल उठे। अधिसंख्य अभ्यर्थियों ने इसे अपने परिवार में पहली सरकारी नौकरी बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार जताया।

सुचिता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई प्रक्रिया

चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं को अवसर मिल रहा है। प्रयागराज की महिमा यादव ने कहा कि वर्ष 2006 के बाद इतने बड़े स्तर पर सीधी भर्ती होना युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है। पूरी प्रक्रिया बेहद सुचिता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

तेजतर्रार और तुरंत निर्णय लेने वाले सीएम

एटा के कुशाल चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करना उनके लिए गर्व का क्षण है। योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए गुंडों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिससे प्रदेश भयमुक्त बना है। उन्होंने मुख्यमंत्री को तेजतर्रार, तुरंत निर्णय लेने वाला और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने वाला नेता बताया। प्रयागराज के सौरभ मिश्रा ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। पुलिस बल की संख्या और संसाधनों में वृद्धि कर अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री की निर्भीक कार्यशैली युवाओं को प्रेरित करती है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रदेश में आया बड़ा बदलाव

प्रयागराज की अदिति राठौर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। आज महिलाएं खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। मुख्यमंत्री के फास्ट रिएक्शन और तत्काल कार्रवाई की नीति से कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है। गोरखपुर की शालू गुप्ता और अयोध्या की सपना पांडेय ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। वहीं अभिषेक कुमार ने कहा कि योगी सरकार में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, इसी वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में सेवा का अवसर मिला है। अलीगढ़ के अरविंद ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाकर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि मेहनत करते रहें, सरकार लगातार रोजगार के अवसर दे रही है।

प्रशिक्षण लेकर करेंगे प्रदेश की सेवा

झांसी के विशाल कुमार शर्मा ने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलना जीवन का यादगार दिन है और अब सभी प्रशिक्षण लेकर सेवा के लिए तैयार होंगे। वहीं हेवल कुमार रत्नागर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही। एटा के रामहरि ने कहा कि रेडियो एवं दूरसंचार विभाग में चयन उनके परिवार के लिए खुशी का बड़ा अवसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रतिभा और मेहनत को सम्मान मिल रहा है।

संक्षिप्त ख़बरें

स्विस कोर्ट का भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय महाघोटाले में बड़ा फैसला, उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी के खिलाफ मुकदमा खारिज

स्विट्जरलैंड के बेलिनज़ोना (Bellinzona) शहर की एक अदालत ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की बेटी गुलनारा करीमोवा के खिलाफ चल रहा मुकदमा खारिज कर दिया। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी से जुड़ा था, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर के लेन-देन और 'क्रिमिनल संगठन' नाम के कथित आपराधिक नेटवर्क की जांच हो रही थी। यह ट्रायल 22 मई तक चलने वाला था, लेकिन शुरू होने के एक दिन बाद ही इसे समाप्त कर दिया गया।अदालत ने कहा कि करीमोवा फिलहाल अपने देश उज्बेकिस्तान में जेल में हैं और वहां की सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी सजा दिसंबर 2028 तक पूरी होगी। ऐसे में उन्हें स्विट्जरलैंड लाकर सुनवाई में शामिल कराना संभव नहीं था। इसी कारण अदालत ने माना कि बिना आरोपी की मौजूदगी के ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता।इसके अलावा, जज ने यह भी कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोप अब 'statute of limitations' यानी कानूनी समयसीमा से बाहर हो चुके हैं, इसलिए केस को आगे जारी रखना संभव नहीं है। गौरतलब है कि करीमोवा को उज्बेकिस्तान में 2015 में दोषी ठहराया गया था। शुरुआत में उन्हें घर में नजरबंद रखा गया, लेकिन 2019 में नियम तोड़ने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल वह 13 साल की सजा काट रही हैं, जिसमें संगठित अपराध, जबरन वसूली और गबन जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि, यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्विस प्राइवेट बैंक Lombard Odier और उसके एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ ट्रायल अभी जारी रहेगा। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि बैंक ने इस कथित घोटाले से जुड़े पैसे को छिपाने में अहम भूमिका निभाई। बैंक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला सिर्फ 'संगठनात्मक कमियों' से जुड़ा है, न कि सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होने से।

चुनाव प्रचार खत्म होते ही जयराम रमेश ने उठाई महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद अब सरकार को महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के बारे में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'अपने व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का उपयोग करने के बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना चाहिए।' 'मुख्य विपक्षी दल ने महिला आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने के बाद एक बार फिर उठाई है। उसने और कई अन्य विपक्षी दलों ने पहले भी सरकार से यह आग्रह किया था कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार संपन्न होने के बाद महिला आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सरकार महिला आरक्षण को वर्ष 2029 से लागू करने और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद के बीते बजट सत्र में लाई थी, हालांकि यह पारित नहीं हो पाया। विपक्ष ने यह कहते हुए इसका पुरजोर विरोध किया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपा जा रहा है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'अब जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और लोकसभा सीटों के खतरनाक परिसीमन को अंजाम देने की उनकी चाल विपक्षी एकजुटता के कारण बुरी तरह विफल हो गई है, तो प्रधानमंत्री के लिए वह करने का समय आ गया है जो विपक्ष एकजुट होकर मार्च, 2026 के मध्य से लगातार मांग कर रहा है।' उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 2029 से लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या के साथ कैसे लागू किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'यह संभव है। यह वांछनीय है। यह जरूरी है।' रमेश ने कहा, 'संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण कभी मुद्दा नहीं था। तब एजेंडा केवल प्रधानमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के लिए परिसीमन था। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत की महिलाओं का उपयोग करने के अपने पापों का प्रायश्चित करें और उन्हें न्याय प्रदान करें।'

योग के बाद अब शिक्षा क्रांति पर जोर... लखनऊ में भारतीय शिक्षा बोर्ड ऑफिस शुरू, स्वामी रामदेव रहे मौजूद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी, स्वामी रामदेव, विशिष्ट अतिथि डॉ एनपी सिंह सहित संतों के सानिध्य में भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रांतीय कार्यालय क्रिश्चयन कॉलेज लखनऊ के प्रांगण में खुला है। इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने कहा कि जिस तरह से योग क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह लखनऊ की धरा से शिक्षा की क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जिसके मूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड है। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ने वाला कोई बच्चा आतंकवादी और व्यवभिचारी नहीं बनेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड देश ही नहीं दुनिया तक अपनी डंका बजायेगा। मैकाले के पाप को हम मिटा कर रहेंगे। मुख्य अतिथि मंत्री माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, वह दिशाहीन हो चुकी है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर वह प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के बच्चे अपने माता-पिता को सुबह उठकर प्रणाम करना भूल चुके हैं। क्या ऐसी शिक्षा की कल्पना हमने की थी। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत जो बीड़ा उठाया है, वह निश्चित तौर पर बच्चों के चरित्र निर्माण करेगा।

भारतीय शिक्षा बोर्ड संतों की लीला है-गुलाब देवी

उन्होंने आश्वस्त किया कि उत्तरप्रदेश सरकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो भी सहयोग होगा, वह सरकार के स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड तो संतों की लीला है. जहां स्वामी रामदेव जैसे संत हो, वहां का बोर्ड निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने गुरु और डाक्टर का उदाहरण दिया. कहा कि गुरु बच्चों के जीवन में आध्यात्मिकता लाता है और बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. इसलिए शिक्षकों का आचरण और व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए जबकि डाक्टर भी कुछ इसी तरह की भूमिका निभाता है. वह हमारे जीवन को बचाता है. उस वक्त हम अपना पूरा समर्पण डाक्टर को कर देते हैं. स्वामी रामदेव ने कहा कि आज पूरी दुनिया की स्थिति शिक्षा को लेकर बेहद खराब हो चुकी है. माता-पिता चिंतित है कि उनका बेटा आज की शिक्षा लेकर क्या बनेगा क्योंकि आज मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से बच्चे डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं. जिसकी वजह से वह संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं. नतीजा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बीड़ी, सिगरेट और शराब पी रहे हैं. ऐसे में संस्कारवान और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना कैसे की जा सकती है?

विदेशी शिक्षा पद्धति में संशोधन की जरूरत

इसी दौरान उन्होंने बचपन में एलन मस्क की पिटाई का संदर्भ भी जोड़ा. जिसकी वजह से आज भी उनमें कहीं न कहीं गुस्सा दिखाई देता है. स्वामी रामदेव ने कहा कि सब चीजों से बच्चों को बचाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है. भारतीय शिक्षा बोर्ड निश्चित तौर पर राष्ट्र का निर्माण करेगी. उन्होंने कहा कि मैकाले ने जो पाप किया था, उसे भारतीय शिक्षा बोर्ड के जरिए ही खत्म किया जा सकता है. आज 190 साल बाद मैकाले के पाप को हम याद कर रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि 21 वीं सदी में भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो यात्रा प्रारंभ हुई है. वह नया भारत का निर्माण करेगी. इसमें सभी की आहुति की जरूरत होगी. स्वामी रामदेव ने कहा कि इस साल एक लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा. इसमें सबसे अधिक संख्या उत्तरप्रदेश की होगी. उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड आधुनिक और प्राचीन शिक्षा का बेजोड़ संगम है. इससे देश में अच्छे नागरिक तैयार होंगे. देश ही नहीं दुनिया तक हम इसे लेकर जाएंगे. 21 वीं सदी का कोई बोर्ड होगा तो वह भारतीय शिक्षा बोर्ड ही होगा. विशिष्ट अतिथि भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एनपी सिंह ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने शिक्षा बोर्ड के गठन को लेकर भी अहम जानकारी दी. कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किसी धर्म, पंत या मजहब का नहीं है. यह सभी 150 करोड़ भारतीयों का बोर्ड है. उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय को लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है. इस दौरान डॉ महेन्द्र सिंह, अवध ओझा ने भी अपनी ओजस्वी संदेश और शुभकामनाएं दी.

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, तत्काल पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन में FNB शुरू, गंभीर बच्चों को मिलेगा तुरंत इलाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली में बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTBH) में पीडियाट्रिक्स (इमरजेंसी मेडिसिन) में FNB (फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड) कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रतिवर्ष 2 सीटें निर्धारित होंगी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बाल चिकित्सा आपातकालीन देखभाल को और ज्यादा मजबूत करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है. यह कदम विशेषज्ञ प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाएगा और गंभीर अवस्था में बच्चों को समय पर और बेहतर उपचार सुनिश्चित करेगा. दरअसल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हर वर्ष लगभग 30000 से लेकर 35000 बाल आपातकालीन मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसके मद्देनजर पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन में सुपर-स्पेशियलिटी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इस कार्यक्रम के शुरू होने से इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के इमरजेंसी इलाज में भी मदद मिलेगी.

जानें कैसे संचालित होता है FNB कार्यक्रम

दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह FNB (फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड) कार्यक्रम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस (NBE) के अंतर्गत संचालित होता है, जो दो वर्ष का पोस्ट-MD सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स है और वरिष्ठ रेजिडेंसी के समकक्ष है. प्रशिक्षुओं को मौजूदा रिक्त वरिष्ठ रेजिडेंट पदों की जगह समायोजित किया जाएगा, जिससे उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

यह फैसला दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत करने और उन्नत चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है.

पाकिस्तान के कराची में बिजली का महासंकट: भीषण गर्मी में सड़कों पर उतरे लोग, लगा भारी जाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में बिजली की भारी किल्लत के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रेलवे कॉलोनी के निवासियों ने पिछले कई दिनों से जारी बिजली कटौती के विरोध में शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे शहर की रफ्तार थम गई।

जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त

भीषण गर्मी के बीच पिछले एक हफ्ते से बिजली न मिलने के कारण महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने महत्वपूर्ण रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जिससे आई. आई. चुंदरीगर रोड और डॉ. जियाउद्दीन रोड जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

आश्वासन के बाद खुला जाम

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे तंग आकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और ट्रैफिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और यातायात सामान्य हो सका।

अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर जान जानलेवा हमले

[अब्राहम लिंकन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सुरक्षा में चूक।]

अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमलों का इतिहास लोकतांत्रिक व्यवस्था की जटिलताओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों का एक गंभीर अध्याय रहा है। जिसकी शुरुआत अब्राहम लिंकन की हत्या से मानी जाती है 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डी.सी. के फोर्ड्स थिएटर में नाटक देखते समय अभिनेता जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मार दी, जो गृहयुद्ध के बाद के तनावपूर्ण माहौल और दक्षिणी असंतोष का परिणाम था। इसके बाद 1881 में जेम्स ए गारफील्ड को चार्ल्स जे गेतयु ने गोली दागी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और यह घटना राजनीतिक संरक्षण से उपजे गहरे असंतोष को दर्शाती है।1901 में विलियम मेकेनी की हत्या लिओन ज़ोलगोस द्वारा की गई, जिसने अराजकतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर यह हमला किया था। 20वीं सदी में सबसे चर्चित घटना 1963 में जॉन एफ केनेडी की हत्या है, जब ली हार्वे ओसवाल्ड ने टेक्सास के डलास में गोली चलाई, यह घटना एसेसिनेशन का जॉन एफ केनेडी के रूप में इतिहास में दर्ज है और आज भी इसके षड्यंत्र सिद्धांतों पर बहस जारी है। हालांकि हर हमला सफल नहीं रहा, 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट पर चुनाव अभियान के दौरान गोली चलाई गई लेकिन वे बच गए थे और घायल अवस्था में भाषण भी दिया, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस का प्रतीक बन था।

1933 में राष्ट्रपति बनने से रूजवेल्ट सेकंड पर गोसेपी जेंगरा ने गोली चलाई, हालांकि निशाना चूक गया और शिकागो के मेयर की मृत्यु हो गई। 1950 में हेनरी ट्रूमैन पर प्लेयर हाउस के बाहर हमलावरों ने गोलीबारी की, जो प्यूर्टो रिकन राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन ट्रूमैन सुरक्षित बच गए। 1975 में गेराल्ड फोर्ड पर दो अलग-अलग महिलाओं ने हमले किए, जो उस समय के सामाजिक उथल-पुथल और अतिवादी मानसिकता को दर्शाते हैं। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर गोली चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन वे सुरक्षित बच गए थे, यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा का कारण बनी।आधुनिक समय में भी खतरे समाप्त नहीं हुए हैं, 21वीं सदी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैलियों के दौरान हमले या प्रयासों की खबरें सामने आई, और वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में एक समारोह के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य सुरक्षित रहे। यह सारी घटनाएं बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसात्मक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं।

इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अमेरिका की खुफिया एजेंसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसकी स्थापना मूलतः वित्तीय अपराधों की जांच के लिए हुई थी लेकिन बाद में राष्ट्रपति सुरक्षा इसकी प्रमुख जिम्मेदारी बन गई। इन हमलों के पीछे विभिन्न कारण रहे हैं राजनीतिक असंतोष, वैचारिक चरमपंथ, मानसिक अस्थिरता, नस्लीय तनाव, और कभी-कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रसिद्धि पाने की चाह जो अमेरिकी समाज के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं। यह भी अत्यंत उल्लेखनीय है कि प्रत्येक घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल और खुफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ किया गया, जैसे खुले मंचों पर राष्ट्रपति की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बुलेटप्रूफ वाहनों और जैकेट्स का उपयोग, तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करना आदि फिर भी लोकतांत्रिक समाज में जनता से सीधा संपर्क बनाए रखना एक चुनौती बना रहता है, क्योंकि सुरक्षा और लोकतांत्रिक खुलापन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र में भी सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि समाज की वैचारिक दिशा, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संतुलन का भी दर्पण है, जहां हर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों पर भी आघात होता है।

अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र के सर्वाधिक सुरक्षित देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हो सकते हैं और उनकी जान भी जाती रही है तो कल्पना कीजिए कि अन्य विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय प्रमुख कितने सुरक्षित हैं। वैसे भी राजनीति कांटों से भर तक माना जाता है और राजनेताओं की जिंदगी भी असुरक्षित ही मानी गई है। इसीलिए सुरक्षात उपकरणों उपाय और सिद्धांतों को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संजीव ठाकुर

एक वोट का सम्मान और लोकतंत्र की विराट शक्ति मतदान केंद्र का संदेश जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बना

गीर के घने जंगलों के बीच स्थापित मतदान केंद्र केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का जीवंत उदाहरण है। जब एक ही मतदाता के लिए पूरा मतदान केंद्र बनाया जाता है तो यह स्पष्ट संदेश देता है कि इस देश में हर नागरिक का वोट बराबर महत्व रखता है। बाणेज क्षेत्र में एकमात्र मतदाता हरिदास बापू के लिए चुनाव आयोग द्वारा की गई यह व्यवस्था दिखाती है कि लोकतंत्र केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान की भावना है।

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के इस दूरस्थ इलाके में जहां पहुंचना भी आसान नहीं है वहां चुनाव कर्मियों का जाना और पूरी प्रक्रिया को निभाना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और समर्पण का उदाहरण है। यहां न तो भीड़ है और न ही राजनीतिक शोर लेकिन फिर भी मतदान की पूरी प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी किसी बड़े शहर के मतदान केंद्र पर होती है। यह दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र हर परिस्थिति में अपने मूल सिद्धांतों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परंपरा नई नहीं है बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है। पहले भरतदास बापू इस केंद्र के एकमात्र मतदाता थे और उनके बाद उनके शिष्य हरिदास बापू इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का मतदान नहीं बल्कि एक परंपरा का निर्वहन है जो यह बताती है कि लोकतंत्र में भागीदारी एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों नागरिक को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए।

घने जंगलों में वन्यजीवों के बीच मतदान केंद्र स्थापित करना आसान नहीं होता। चुनाव कर्मियों को कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ता है और हर छोटी बड़ी व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी यह सब केवल एक वोट के लिए किया जाता है। यह उस सोच को दर्शाता है जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हरिदास बापू का यह कहना कि जब सरकार एक व्यक्ति के लिए इतनी व्यवस्था कर सकती है तो हर नागरिक को मतदान करना चाहिए एक गहरी बात है। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। अक्सर देखा जाता है कि शहरों में लोग मतदान के दिन घर पर ही रहते हैं या छुट्टी का आनंद लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह उदाहरण एक आईना है जो उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाता है।

गुजरात में हुए स्थानीय स्वराज चुनाव भी इस बात का प्रमाण हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था बनाए रखते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने मतदान किया और औसतन अच्छा प्रतिशत दर्ज हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो उत्साह और भी अधिक देखने को मिला जहां लोगों ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग किया। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें गांवों में कितनी मजबूत हैं। महानगरपालिकाओं में अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत जरूर चिंता का विषय है लेकिन यह भी एक अवसर है सुधार का। जब एक व्यक्ति जंगल में मतदान कर सकता है तो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए मतदान करना और भी आसान होना चाहिए। यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।

चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था के रूप में उसने बार बार यह साबित किया है कि वह हर परिस्थिति में लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है। चाहे वह दूरदराज का इलाका हो या भीड़भाड़ वाला शहर हर जगह एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यही कारण है कि भारत का चुनावी तंत्र विश्व में सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय माना जाता है। कई बार राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन बाणेज जैसे उदाहरण इन आरोपों का सीधा जवाब देते हैं। जब एक वोट के लिए इतनी मेहनत और संसाधन लगाए जाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्य के प्रति कितना गंभीर है। ऐसे में बिना ठोस आधार के आरोप लगाना न केवल संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाता है बल्कि लोकतंत्र के प्रति लोगों के विश्वास को भी कमजोर करता है।

यह जरूरी है कि राजनीतिक दल और नेता अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करें। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन वह तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। निराधार आरोप केवल भ्रम फैलाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। बाणेज का यह उदाहरण बताता है कि सच्चाई क्या है और व्यवस्था कितनी मजबूत है। मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। यह वह माध्यम है जिसके जरिए नागरिक अपनी सरकार चुनते हैं और अपने भविष्य को आकार देते हैं। जब लोग मतदान नहीं करते तो वे अपने अधिकार को खो देते हैं और दूसरों को निर्णय लेने का मौका दे देते हैं। इसलिए हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि उसका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब तकनीक और सुविधा हर जगह उपलब्ध है तब भी अगर लोग मतदान से दूर रहते हैं तो यह चिंताजनक है। बाणेज का मतदान केंद्र हमें यह सिखाता है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकार का सम्मान करें और हर चुनाव में भाग लें।झ अंत में यह कहा जा सकता है कि गिर के जंगल में स्थापित यह मतदान केंद्र केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचार है। यह विचार है समानता का अधिकार का और जिम्मेदारी का। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का है। इसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जब एक व्यक्ति के लिए पूरा मतदान केंद्र बनाया जा सकता है तो यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तभी हम एक मजबूत और जागरूक समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां हर आवाज सुनी जाएगी और हर वोट की कीमत होगी।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य: एक वैश्विक मानवीय प्रतिबद्धता

विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। यह केवल एक औपचारिक अवसर नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा का एक गंभीर स्मरण भी है। इस दिन का उद्देश्य कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं, बीमारियों और जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सरकारों, संस्थाओं और समाज को यह याद दिलाना है कि आर्थिक विकास का वास्तविक आधार सुरक्षित और स्वस्थ श्रमिक ही होते हैं।

विश्व स्तर पर श्रमिकों की स्थिति पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार हर वर्ष लगभग 2.78 मिलियन लोग कार्यस्थल से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा करीब 374 मिलियन गैर घातक दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनसे लोगों को गंभीर चोटें और लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं। ये आँकड़े यह दर्शाते हैं कि कार्यस्थल की सुरक्षा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है।

विकासशील देशों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। भारत जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ न तो उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते हैं और न ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ। खेतों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक, छोटे कारखानों के कर्मचारी और घरेलू कामगार अक्सर जोखिम भरे वातावरण में काम करते हैं। कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे किन खतरों के बीच काम कर रहे हैं। यह अज्ञानता और संसाधनों की कमी मिलकर दुर्घटनाओं की संभावना को और बढ़ा देती है।

कार्यस्थल पर सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। आधुनिक समय में काम का दबाव, लंबे समय तक काम करना, अस्थिर रोजगार और आर्थिक असुरक्षा जैसे कारक मानसिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं के कारण हर वर्ष लगभग 12 बिलियन कार्य दिवसों का नुकसान होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी कार्यस्थल की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

तकनीकी प्रगति ने जहाँ एक ओर काम को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर नए प्रकार के जोखिम भी उत्पन्न किए हैं। मशीनों का अधिक उपयोग, रसायनों का संपर्क, और डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता ने नए स्वास्थ्य खतरे पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आँखों और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों में रसायनों के संपर्क से गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए, सुरक्षा उपायों को समय के साथ अद्यतन करना आवश्यक है।

विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका मतलब यह है कि दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही ऐसे उपाय किए जाएँ जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाए। इसके लिए जोखिम का आकलन, सुरक्षा प्रशिक्षण, उचित उपकरणों का उपयोग और नियमित निरीक्षण जैसे कदम आवश्यक हैं। यदि किसी कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, तो न केवल श्रमिक सुरक्षित रहते हैं बल्कि उत्पादकता भी बढ़ती है और आर्थिक नुकसान कम होता है।

सरकारों की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मजबूत कानून, प्रभावी निगरानी और सख्त कार्यान्वयन के बिना कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। भारत में भी श्रम कानूनों के माध्यम से सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनका सही क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। कई छोटे उद्योगों में नियमों का पालन नहीं किया जाता और निरीक्षण की प्रक्रिया भी पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार, उद्योग और समाज के बीच सहयोग आवश्यक है।

नियोक्ताओं की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि श्रमिक केवल उत्पादन का साधन नहीं बल्कि संगठन की सबसे मूल्यवान पूंजी हैं। सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। उचित प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से श्रमिकों का विश्वास बढ़ता है और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है।

श्रमिकों की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार दुर्घटनाएँ इसलिए होती हैं क्योंकि श्रमिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते या उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती। यदि श्रमिक अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक हों, तो वे खुद को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। कोविड 19 महामारी ने कार्यस्थल सुरक्षा के महत्व को और अधिक स्पष्ट कर दिया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों ने अत्यधिक जोखिम के बीच काम किया। इससे यह सीख मिली कि आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

जलवायु परिवर्तन भी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। बढ़ते तापमान, अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण श्रमिकों के लिए काम करना कठिन होता जा रहा है। विशेष रूप से खुले में काम करने वाले लोगों जैसे किसान और निर्माण श्रमिकों के लिए यह एक गंभीर समस्या है। अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रेस, निर्जलीकरण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। इसलिए जलवायु के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियाँ बनाना आवश्यक है। इस दिवस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें मानवीय मूल्यों की याद दिलाता है। आर्थिक विकास, उत्पादन और लाभ तभी सार्थक हैं जब वे मानव जीवन की सुरक्षा और सम्मान के साथ जुड़े हों। यदि किसी भी विकास की कीमत मानव जीवन हो, तो वह विकास अधूरा है। इसलिए यह दिन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानजनक परिस्थितियों में काम कर सके। भविष्य की दिशा में देखते हुए यह आवश्यक है कि हम तकनीक, नीति और जागरूकता को एक साथ लेकर चलें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन जैसे क्षेत्र कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही नए प्रकार के कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होगी। यदि हम इन परिवर्तनों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम एक ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो सुरक्षित, स्वस्थ और समावेशी हो।

अंततः विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक संकल्प है। यह संकल्प है कि हर श्रमिक का जीवन मूल्यवान है, हर कार्यस्थल सुरक्षित होना चाहिए और हर व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में काम करने का अधिकार है। जब तक दुनिया का हर श्रमिक सुरक्षित नहीं होता, तब तक यह प्रयास जारी रहना चाहिए। यही इस दिन का वास्तविक संदेश है और यही मानवता की सच्ची प्रगति का आधार भी है।

महेन्द्र तिवारी

आग उगलती भीषण गर्मी में प्यासे कंठों की कौन सुने दास्तां

देश के कई राज्यों में इस समय भीषण और भयावह गर्मी का प्रकोप जारी है। हर वर्ष तापमान अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाइयां छू रहा है। आसमान से बरसती आग ने मानो समस्त जीव-जंतुओं के कंठ सूखा दिए हैं। यह बढ़ती हुई भीषण गर्मी कहीं न कहीं मानव द्वारा किए जा रहे पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति-विनाश का परिणाम है। इसी के चलते जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश के कारण अनेक प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे मूक वन्यजीवों के जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी प्रकृति के समस्त जीवों की मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन विडंबना यह है कि जब यही आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो जीवों के अस्तित्व पर संकट गहराना स्वाभाविक है।

यह स्वीकार करना होगा कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं कि वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते होंगे। मानव जीवन के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। विशेषकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की 'नल-जल योजना' एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक गाँवों में बनी पानी की टंकियाँ केवल दिखावा बनकर रह गई हैं। ये टंकियाँ प्यासे कंठों को राहत देने के बजाय व्यवस्था की खामियों का प्रतीक बनती जा रही हैं।

पानी हर जीव की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि इसी आवश्यकता की पूर्ति में कमी रह जाए, तो यह न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि अक्षम्य अपराध के समान है। भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर निकलने से बचते हैं, तब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मीलों दूर से पानी लाने को विवश होते हैं। जल संकट के कारण मूक पशु-पक्षियों का जीवन बचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।

प्रकृति-विनाश के चलते बढ़ती गर्मी और अस्तित्व बचाने के लिए भटकते वन्यजीव–ये दोनों ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं। ऐसे में सरकार और समाज को मिलकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक मानव और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यदि इस दिशा में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, तो देश के हर कोने में सभी जीवों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा, हर वर्ष की भाँति आग उगलती गर्मी में प्यासे मूक प्राणियों की दास्तां अधूरी ही रह जाएगी।

अरविंद रावल

महंगी किताबें, अभिभावकों की जेब पर डाल रही डाका

भारत में निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने की प्रथा एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एचआरसी) ने हाल ही में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि निजी स्कूल एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की जगह महंगे प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें अनिवार्य कर अभिभावकों को हजारों रुपये अतिरिक्त खर्च करने को मजबूर कर रहे हैं।

एनसीईआरटी किताबें सरकारी सब्सिडी के कारण सस्ती होती हैं। प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) के लिए एनसीईआरटी किताबों का पूरा सेट आमतौर पर 200 से 700 रुपये तक आता है। वहीं, निजी प्रकाशकों की किताबों का बंडल 5,000 से 8,000 रुपये या उससे भी अधिक का हो सकता है।

लखनऊ के नीलमठा निवासी प्रिंस लेनिन का मामला इस समस्या का ज्वलंत उदाहरण है। उनके दो बच्चे क्लास 7 और क्लास 3 में पढ़ते हैं। जब वे स्कूल से जुड़ी दुकान क्लेवर पेस बुक स्टोर (वृंदावन सेक्टर-9) से किताबें खरीदने गए, तो दुकानदार ने साफ कहा कि अलग-अलग किताबें नहीं बेची जाएंगी–पूरी सेट और नोटबुक साथ खरीदनी होंगी। लेनिन ने बताया कि उन्होंने अमीनाबाद से नोटबुक आधी कीमत पर बेहतर क्वालिटी में खरीद ली थी, लेकिन स्कूल के दबाव के कारण पूरा सेट लेना पड़ा। ऐसे कई अभिभावक रिपोर्ट करते हैं कि एनसीईआरटी किताबों का पूरा सेट 200-700 रुपये में आ जाता है, जबकि निजी प्रकाशकों का बंडल 5,000 से 10,000 रुपये या उससे ज्यादा का हो जाता है।

एक वायरल वीडियो में लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के कैम्ब्रिज सेक्शन में क्लास 5 की एक अंग्रेजी किताब (बर्लिंगटन इंग्लिश सीरीज) की कीमत 1,035 रुपये बताई गई, जिसने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। अभिभावक पूछ रहे हैं कि जब एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो किया जाता है, तो इतनी महंगी प्राइवेट किताबें क्यों थोपी जा रही हैं? कई स्कूल हर साल नई एडिशन लाकर पुरानी किताबों को इस्तेमाल करने नहीं देते, जिससे खर्च और बढ़ जाता है शिक्षक कभी-कभी एनसीईआरटी किताबों को बोर्ड परीक्षा के लिए अपर्याप्त बताकर निजी किताबों का प्रचार करते हैं। यह प्रथा सीबीएसई के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीबीएसई ने अगस्त 2024 में अपने एफिलिएशन बायलॉज में संशोधन कर कक्षा 9 से 12 के लिए एनसीईआरटी किताबें अनिवार्य कर दी हैं, जबकि कक्षा 1 से 8 के लिए इनका उपयोग दृढ़ता से सलाह दिया गया है। पूरक सामग्री की अनुमति है, लेकिन एनसीईआरटी किताबें मुख्य आधार होनी चाहिए। दिल्ली शिक्षा विभाग ने भी अगस्त 2024 में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि प्राथमिक कक्षाओं में एनसीईआरटी/एससीईआरटी के अलावा अन्य किताबें अनिवार्य नहीं की जा सकतीं। ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि निजी स्कूल केवल एनसीईआरटी किताबें ही लगाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। पटना, भोपाल और अन्य शहरों में रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर निजी स्कूल इन दिशानिर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं।

लखनऊ में प्रशासन की सख्ती

लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने हाल ही में फीस रेगुलेटरी कमिटी की बैठक में स्पष्ट आदेश दिए कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी विशिष्ट

दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उल्लंघन पर 5 लाख तक जुर्माना या स्कूल की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के गैर-सरकारी निजी स्कूल संघ (यूपीएसए) ने भी घोषणा की है कि सदस्य स्कूल अब अभिभावकों को किसी खास ब्रांड या दुकान से किताबें खरीदने के लिए नहीं कहेंगे और किताबें बार-बार नहीं बदलेंगे। फीस बढ़ोतरी भी 2026-27 सत्र के लिए 7.5% तक सीमित रखी गई है। फिर भी, कई अभिभावक शिकायत करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर स्कूलों की मनमानी जारी है। शिक्षक कभी-कभी क्लास में एनसीईआरटी किताबों को अपर्याप्त बताकर प्राइवेट किताबों का प्रचार करते हैं। कुछ स्कूल कमीशन के चक्कर में प्राइवेट पब्लिशर्स से टाई-अप रखते हैं, जिससे एनसीईआरटी की सस्ती किताबें (सरकारी सब्सिडी वाली) हाशिए पर चली जाती हैं।

आरटीई एक्ट और शिक्षा की समानता पर असर

राइट टू एजुकेशन (आरटीई) एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम और किताबें एनसीईआरटी/एससीईआरटी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा में uniformity लाना, गुणवत्ता बनाए रखना और लागत कम करना है। निजी स्कूलों में प्राइवेट किताबें लगाने से न केवल आरटीई का उल्लंघन होता है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शिक्षा और महंगी हो जाती है। एनएचआरसी ने कहा है कि यह अभिभावकों पर 'अत्यधिक वित्तीय बोझ' डालता है और एनईपी 2020 के मानदंडों का भी विरोध करता है। आयोग ने राज्यों से पूछा है कि क्या उन्होंने आरटीई धारा 29 के अनुपालन के लिए कोई निरीक्षण या ऑडिट किया है। शिक्षाविदों का कहना है कि कुछ स्कूल किताब बिक्री से अतिरिक्त कमाई करते हैं, क्योंकि स्कूल फीस पर सख्त नियम हैं। यह 'बिजनेस वेंचर' की तरह काम करता है, जबकि स्कूलों को सामुदायिक सेवा के रूप में चलना चाहिए। कई अभिभावक रिपोर्ट करते हैं कि किताबों के अलावा यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामान भी स्कूल निर्दिष्ट दुकानों से ही खरीदने पड़ते हैं, जिससे सालाना खर्च कई हजार रुपये बढ़ जाता है।

बढ़ती शिक्षा लागत: एक व्यापक समस्या भारत में निजी स्कूलों की फीस और किताबों की लागत तेजी से बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र सालाना शिक्षा संबंधी खर्च औसतन 2,863 रुपये है, जबकि निजी स्कूलों में यह 28,693 रुपये तक पहुंच जाता है–लगभग 10 गुना अधिक। किताबें और स्टेशनरी सरकारी स्कूलों में कुल खर्च का 40% हिस्सा हैं, जबकि निजी स्कूलों में फीस मुख्य बोझ है। मध्य वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बोझ शिक्षा को 'सुविधा' की बजाय 'लग्जरी' बना रहा है।

लखनऊ और उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में भी अभिभावक इस समस्या से जूझ रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत में किताबों की लंबी लिस्ट और उनकी कीमतें देखकर माता-पिता परेशान हो जाते हैं। कुछ राज्यों में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को लागू करने की बात भी उठी है, ताकि बच्चों के बैग का वजन कम हो और अनावश्यक किताबें न लगाई जाएं।

समाधान की दिशा में कदम

एनएचआरसी ने केंद्र और राज्यों से 30 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि वे एनसीईआरटी/एससीईआरटी

किताबों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि:

- सभी सीबीएसई/निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर निर्धारित किताबों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए।
- स्कूल परिसर में किताबें या यूनिफॉर्म बेचना बंद किया जाए।
- उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, जैसे मान्यता रद्द करना।
- एनसीईआरटी किताबों की गुणवत्ता में सुधार और पूरक सामग्री के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश।

शिक्षा विशेषज्ञ एमके श्रीधर (NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी सदस्य) का कहना है कि कक्षा 8 तक निजी प्रकाशकों को कुछ स्वतंत्रता दी जा सकती है, लेकिन एनसीईआरटी को मुख्य आधार बनाना चाहिए ताकि रचनात्मकता बनी रहे और लागत नियंत्रित रहे। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि शिक्षा की समानता और गुणवत्ता से जुड़ी है। यदि निजी स्कूलों की यह मनमानी जारी रही, तो मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दूर होती जाएगी। सरकार और नियामक संस्थाओं को अब सख्ती से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि शिक्षा सस्ती, समान और गुणवत्तापूर्ण बने। अभिभावकों को भी जागरूक होकर स्कूलों से एनईपी और सीबीएसई नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग करनी चाहिए।

लेखक/संपादक: राजीव शुक्ला

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

कोतवाली में 81 नए पुलिसकर्मियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कोतवाली में 81 नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें 16 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सोमवार को सभी नव प्रशिक्षित जवानों ने कोतवाली में अपनी आमद दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड ड्यूटी की बारीकियों से अवगत कराते हुए अनुशासन और व्यवहार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही जवानों को रहने और खाने की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके भी समझाए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को विशेष जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नई तैनाती के बाद कोतवाली में पुलिस बल की संख्या अब करीब 200 हो गई है। इससे क्षेत्र में गश्त बढ़ेगी और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

घर में घुसे युवक ने मासूम गले पर चाकू रखकर महिला को दी जान से मारने की धमकी

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने घर में घुसकर महिला और उसके ढाई साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बन्नामऊ गांव निवासी प्रीती पत्नी सूरज ने पुलिस को बताया कि मौसी पक्ष से जुड़े रिश्तेदार सचिन निर्मल पुत्र शिवकुमार उर्फ पप्पू निवासी चोरहनखेड़ा थाना गुरुबख्शगंज अचानक उसके घर में घुस आया। आरोप है कि उसने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट की। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके ढाई साल के बेटे रूद्र को भी नहीं बख्शा। उसने मासूम के गले पर चाकू रख दिया। जान से मारने की धमकी दी। घटना से महिला सहम गई। बच्चे के गले पर चोट के निशान भी मिले है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब जाकर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला और बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर मेडिकल परीक्षण कराया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है।

शांति भंग की आशंका में 6 गिरफ्तार, 19 वाहनों का चालान

भदोही। जनपद पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के तहत कार्रवाई करते हुए शांति भंग की आशंका में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय भेजा गया। पुलिस के अनुसार, थाना कोईरौना क्षेत्र में दो, थाना चौरी क्षेत्र में एक तथा थाना सुरियावां क्षेत्र में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं यातायात पुलिस ने भी नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाते हुए अभियान चलाया। इस दौरान 18 दोपहिया और 1 चारपहिया समेत कुल 19 वाहनों का चालान कर 19 हजार रुपये का समन शुल्क वसूला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अशोक उपाध्याय स्थायी निवासी ई 4 एम -42 अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश मेरी पुत्री इशिता उपाध्याय निवासी ई 4 एम -42 अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल का अंक पत्र / प्रमाणपत्र जिसका रोल नंबर-1241110683 एवं प्रमाण पत्र क्रमांक -24172370 कही खो गयी है काफी तलाश के बाद भी मुझे नहीं प्राप्त हो पायी है अतः यदि किसी को कही मिल जाती है तो कृपया उक्त पते पर देने की कृपा करे।

पंचायत चुनाव से पहले बिना कार्यों के भुगतान कर चुनाव भुनाने की तैयारी

- रूपईडीह ब्लॉक में बड़ा खेल ?
- जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल! रूपईडीह में फर्जी भुगतानों का खेल उजागर
- हैंडपंप रिबोर से लेकर सड़क-नाली तक कागजों में विकास, बिना कार्य निकाले जा रहे लाखों रुपये

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद विकास खंड रूपईडीह में कथित फर्जी भुगतानों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पंचायत सचिव और प्रधान की मिलीभगत से विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर बिना कार्य कराए ही लाखों रुपये का भुगतान निकाल लिया जा रहा है।ग्रामीणों और सूत्रों के अनुसार, भरियालाबेदपुर, बेलवा कर्मडीह , भवानियापुर उपाध्याय, भटपुरवा, तेंदुआचौखड़िया, पचरन, बभनी सराय,देवरिया कला समेत कई ग्राम पंचायतों में हैंडपंप रिबोर और मरम्मत के नाम पर भारी रकम खर्च दिखाई गई है, जबकि कई स्थानों पर हैंडपंप आज भी खराब पड़े हैं या कुछ ही दिनों में फिर से बंद हो जाते हैं। इससे पेयजल संकट और गहरा गया है। इसके अलावा आरोप है कि पंचायत भवन मरम्मत, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट स्थापना, कूप मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के नाम पर भी कागजों में योजनाएं पूर्ण दिखाकर भुगतान निकाल लिया जाता है। जमीनी हकीकत में कई स्थानों पर या तो कार्य शुरू ही नहीं हुए या बेहद घटिया गुणवत्ता के साथ अधूरे छोड़ दिए गए।ग्रामीणों का कहना है कि इन कार्यों से संबंधित फर्मों, टेंडर और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं दी जाती। ना ही कभी गांव में कार्य योजना को लेकर के बैठक भी होती है 'कागजों में सब कुछ पूरा है, लेकिन गांव में विकास कहीं नजर नहीं आता,' ग्रामीणों ने आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि कई मामलों में शिकायतों के बावजूद भी संदिग्ध फर्मों को लगातार भुगतान किया जाता रहा। इससे साफ है कि पूरे प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही या मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का मानना है कि यदि इन सभी कार्यों–हैंडपंप मरम्मत, सड़क और नाली निर्माण, पंचायत भवन मरम्मत आदि–की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए, तो भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खुल सकती है। यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि सरकार की नीतियों के भी सीधे खिलाफ है।

पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण इस पूरे मामले को चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप है कि कागजी विकास दिखाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रूपईडीह ब्लॉक की सभी संदिग्ध ग्राम पंचायतों में हुए भुगतानों, कार्यस्थलों और संबंधित फर्मों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अब बड़ा सवाल यह है— क्या सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीनी स्तर पर भी लागू होगी, या फिर फर्जी भुगतान का यह खेल यूं ही चलता रहेगा?

तहसील परिसर में खराब पड़ा आरओ प्लांट, भीषण गर्मी में पेयजल संकट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। तहसील परिसर में लगा आरओ वाटर कूलर कई वर्षों से खराब पड़ा है, जिससे भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं और फरियादियों को ठंडे पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने परिसर में लगे आरओ प्लांट की जल्द मरम्मत कराए जाने की मांग उठाई है।

तहसील में हर दिन सैकड़ों लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। इनमें कई लोग दूर-दराज क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में पेयजल की उचित व्यवस्था न होना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। बताया जाता है कि तहसील परिसर के अधिवक्ता हाल के पास वर्ष 2019 में तत्कालीन विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा लोगों की सुविधा के लिए दो हजार लीटर क्षमता का आरओ प्लांट और 400 लीटर का चिलर लगवाया गया था। लेकिन वर्तमान में यह पूरी तरह खराब हो चुका है। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आरओ खराब होने के कारण लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री दल बहादुर सिंह ने कहा कि आरओ खराब होने से फरियादियों की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया पहले ही कठिन होती है, ऐसे में पानी की समस्या नई चुनौती बन गई है।

अधिवक्ता पंकज मिश्रा के अनुसार, आरओ की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील आने वाले लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आरओ प्लांट को ठीक कराने की मांग की है।

अमर नगर श्मशान घाट में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान

- इलाके में शोक की लहर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

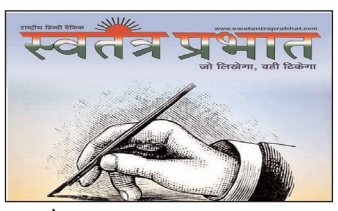

बिसवां/ सीतापुर के अमर नगर मोहल्ले में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव श्मशान घाट में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। मृतक की पहचान संतोष विश्वकर्मा के पुत्र अंकुश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंकुश विश्वकर्मा ने अज्ञात कारणों के चलते मंसाराम श्मशान घाट में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्थानीय लोगों ने जब शव को फंदे से लटका देखा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। ?परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि अंकुश एक मिलनसार युवक था, उसका इस तरह अचानक चले जाना समझ से परे है

मानसिक स्वास्थ्य पर उठ रहे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर युवाओं में बढ़ती निराशा और मानसिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग ने अपील की है कि समाज को युवाओं की मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत है, ताकि ऐसे आत्मघाती कदमों को रोका जा सके। क्षेत्रीय पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

मन लगाकर पढ़ाई करे सफलता के रास्ते खुद आगे खुलते चले जायेंगे-एम दामिनी दास

लहरपुर सीतापुर- मन लगाकर पढ़ाई करें खूब मेहनत करें सफलता के रास्ते खुद ही आगे खुलते चले जाएंगे उक्त विचार उप जिलाधिकारी लहरपुर एम दामिनी दास ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में उच्च अंक अर्जित करने वाली आशी मिश्रा को सम्मानित करते हुए व्यक्त किया उन्होंने बताया जब हम लक्ष्य बनाकर मन लगाकर पढ़ते हैं तो एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। इस मौके पर तहसीलदार लहरपुर योगेश मिश्रा कन्हैया तथा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी मौजूद रहे हसीन अंसारी ने बताया अति शीघ्र ही एक करियर काउंसलिंग मेले का आयोजन लहरपुर क्षेत्र में किया जाएगा जिससे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र एवं छात्रों को अपनी राह चुनने में आसानी होगी और सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।

वे पब्लिक स्कूल में प्रतिभा अलंकरण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन

- मेधावी छात्र-छात्राओं के चेहरे पर खिले प्रशस्ति पत्र सम्मान के मुस्कान भरे रंग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिधौली। कस्बा सिधौली के सिद्धेश्वर मोहल्ला स्थित पावर हाउस के निकट न्यू वे पब्लिक स्कूल में रविवार को प्रतिभा अलंकरण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक सम्मानित व्यक्तित्वों की उपस्थिति ने समारोह को गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद् गुरुजी आर. डी. वर्मा उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. देवेंद्र कश्यप 'निडर', नारी रत्न सामाजिक कार्यकर्ता नीतू वर्मा, तथा मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. चंद्रशेखर प्रजापति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, अभिभावक एवं शिक्षा प्रेमी भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को प्रभावित किया। बच्चों के आत्मविश्वास और मंचीय प्रतिभा ने विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सुंदर झलक प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता डॉ. चंद्रशेखर प्रजापति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो विद्यार्थियों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा पद्धति और विद्यार्थियों की प्रतिभा की मुक्तकंठ से सराहना की। अपने संबोधन में अतिथियों ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि न्यू वे पब्लिक स्कूल कम शुल्क में उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराकर क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा गुणवत्ता और उच्च कोटि के मार्गदर्शन के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम का सफल संचालन आदित्य कुमार द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद अशफाक ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। यह आयोजन विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति विद्यालय प्रबंधन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।

लू की तीव्रता के दृष्टिगत स्वास्थ्य प्याऊ जल, विशेष चिकित्सीय व्यवस्थाएं की जाए

- तीव्रता के दृष्टिगत स्वास्थ्य प्याऊ जल, वाटर कूलर, विशेष चिकित्सीय व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करायें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज- अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्र ने जनपद प्रयागराज में हीट वेव (लू) के दृष्टिगत प्याऊ जल, वाटर कूलर, चिकित्सीय एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में अपर नगर आयुक्त-नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत को सम्बन्धित से समन्वय कर समस्त व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराते हुए जनहित में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी हीट वेव अलर्ट एवं वर्तमान में बढ़ते तापमान का जनपद प्रयागराज में अत्यधिक गर्मी एवं हीट वेव (लू) की तीव्रता को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा हेतु व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें समस्त सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, चौराहे एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में प्याऊ (शीतल पेयजल) की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रमुख स्थानों पर वाटर कूलर/जल टैंकर स्थापित किए जाएं। पेयजल की स्वच्छता, शुद्धता एवं निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नगर निकाय द्वारा नियमित रूप से जल स्रोतों की सफाई एवं रख-रखाव किया जाए। समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में हीट वेव प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। ओआरस, ग्लूकोज, आवश्यक दवाइयां एवं प्राथमिक उपचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जाए। इमरजेंसी वार्ड में पर्याप्त बेड आरक्षित रखे जाएं। 108/102 एम्बुलेंस सेवाओं को पूर्णतः सक्रिय एवं अलर्ट मोड में रखा जाए। स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित की जाए। लू से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरूक करने के लिए माइकिंग, पोस्टर, बैनर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। नागरिकों को दोपहर 12:00 बजे से 04:00 बजे तक अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी जाए। अधिक मात्रा में पानी पीने, हल्के एवं ढीले कपड़े पहनने एवं छाया में रहने हेतु प्रेरित किया जाए। समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रमुख स्थानों पर प्याऊ जल, शर्बत, छाछ आदि का वितरण कराया जाए। राहगीरों, श्रमिकों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु छाया एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था की जाए। प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अधिकतम स्थानों पर सहयोग प्रदान किया जाए। अपर जिलाधिकारी नगर ने समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं का नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा है। कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के कारण मार्ग डायवर्सन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। दिनांक 29.4.2026 को प्रधानमंत्री द्वारा जनपद हरदोई के मल्लांवा में नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण कार्यक्रम के दृष्टिगत कानपुर नगर में नानामऊ से बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) से जनपद हरदोई की तरफ जाने वाले भारी वाहनों का डायवर्जन दिनांक 28.4.2026 को समय सांय 6 बजे से दिनांक 29.04.2026 को समय रात्रि 12 बजे तक संशोधन किया गया है। बिल्हौर की तरफ से आने वाले भारी वाहन नानामऊ तिराहा से बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) होते हुए जनपद हरदोई की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे भारी वाहन नानामऊ से बाये मुड़कर अरौल से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। अरौल की तरफ से आने वाले भारी वाहन नानामऊ तिराहा से बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) होते हुए जनपद हरदोई की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे भारी वाहन नानामऊ तिराहा से यू टर्न लेकर अरौल से लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। कानपुर नगर (शिवराजपुर, चौबेपुर) की तरफ से जाने वाले भारी वाहन नानामऊ तिराहा से बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) होते हुए जनपद नहीं जा सकेंगे, ऐसे भारी वाहन सीधे अरौल से लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगें । उन्नाव परियर पुल से बिठूर की तरफ आने वाले भारी वाहन मंधना तिराहा से अपने गंतव्य को जा सकेगें । चौबेपुर से आने वाले भारी वाहन बिठूर होते हुए उन्नाव की तरफ नहीं जा सकेंगे, ऐसे भारी वाहन चौबेपुर से शिवराजपुर होते अपने गंतव्य को जा सकेंगे। बिठूर तिराहा / ब्लू वर्ड तिराहा से भारी वाहन बिठूर होकर उन्नाव की तरफ नहीं जा सकेंगे, ऐसे भारी वाहन मंधना चौराहा/गंगा बैराज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। यशकोठारी से आने वाले भारी वाहन बिठूर की तरफ नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन ब्लू वर्ड तिराहा एवं मंधना चौरहा से होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

कुम्हारों के लिए सुनहरा मौका, मुफ्त चाक मशीन

देवरिया। परंपरागत कारीगरों और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एक ओर जहां माटीकला से जुड़े कुम्हारों को सरकार मुफ्त में विद्युत चालित चाक मशीन दे रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर भी सामने आया है। जिला ग्रामोद्योग विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45 विद्युत चाक मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएंगी। इसका लाभ 18 से 55 वर्ष के पात्र कुम्हार उठा सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और अंतिम तिथि 27 मई तय की गई है। योजना के जरिए मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं युवाओं के लिए 30 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट के लिए अप्रेंटिसशिप पर चयन होगा। आईटीआई और हाईस्कूल में 60 प्रतिशत अंक वाले 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 13,870 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। एक तरफ सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं को उद्योगों से जोड़ने की पहल कर रही है। अब जरूरत है कि पात्र लोग इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।

प्रसूता के सीने पर बैठने से नवजात की मौत मामले में , DM बदायूं से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। बदायूं जिले की राधिका नर्सिंग होम में प्रसूता के साथ की गई अमानवीयता से नवजात की मौत मामले को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। राज्य परिवर्तन आयोग (स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन) इस मामले की पूरी जांच कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट तीन दिन के अंदर भेजने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। वहीं, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को डीएम बदायूं को भेजे गए पत्र की प्रति अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी दी है। उल्लेखनीय है कि राधिका नर्सिंग होम में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने प्रसूता के सीने पर बैठकर उसका पेट दबाया था, जिससे नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में सीएमओ डॉ. मोहन झा ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादरचौक के चिकित्सा प्रभारी डा. अवधेश सिंह राठौर को दूसरे सीएचसी पर स्थानांतरित कर दिया है। बिना लाइसेंस चल रहे नर्सिंग होम को सील करा दिया है।

एक दर्जन स्कूली वाहनों का चालान,तीन निरुद्ध

- प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भदोही। जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) राम सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्कूली वाहनों और निजी बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 स्कूली वाहनों और बसों का चालान किया गया, जबकि 3 वाहनों को गंभीर अनियमितताओं के चलते निरुद्ध कर दिया गया। कार्रवाई की जद में आने वाले विद्यालयों में डोनिव पब्लिक स्कूल, काशी राज पब्लिक स्कूल, केजी मेमोरियल स्कूल, बीपीएमजी स्कूल और पीस कॉटेज स्कूल समेत अन्य शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि कई वाहनों में आवश्यक दस्तावेज अधूरे पाए गए। इनमें कर अदायगी न होना, वैध परमिट का अभाव, प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र की कमी जैसी खामियां शामिल रहीं, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन हैं। उन्होंने सभी स्कूल बस और निजी बस संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक प्रपत्र तत्काल पूर्ण कराएं। चेतावनी देते हुए कहा गया कि भविष्य में बिना दस्तावेजों के वाहन संचालन पाए जाने पर चालान, वाहन सीज करने और पंजीयन निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।

राहिनी सोलर में डीलर एवं उपभोक्ताओं की बैठक आयोजित

- विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों पर विशेष चर्चा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नैनी,प्रयागराज। राहिनी सोलर के एडीए कॉलोनी स्थित कार्यालय में रविवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'पीएम सूर्य घर योजना' को लेकर सोलर कंपनी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते उपभोक्ताओं को हो रही बड़ी परेशानियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। राहिनी सोलर के सीईओ विकास मिश्रा ने बताया कि सोलर कंपनी के डीलर पूरी तरह से परेशान हो चुके है। कंपनी उपभोक्ताओं के घरों में सोलर इंस्टालेशन कराती है। लेकिन विद्युत विभाग को ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट प्री पेड मीटर के चलते उन्हें बड़ी दिक्कतों का कामना करना पड़ रहा है। अचानक से विद्युत कनेक्शन काट दिया जा रहा है। उनका रिचार्ज पेमेंट माइनस में बताता है। ऐसे में उन्हें भुगतान करने के बाद भी बिजली विभाग की तरफ से बिजली काट दी जा रही है। इस बैठक में 100 से अधिक डीलरों, इनवर्टर निर्माताओं और बैटरी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर कहा कि विभाग में इस समस्या को लेकर जब बात की जाती है तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी ही कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना के तहत हर घर को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युत विभाग की कमियों और लापरवाहियों से उपभोक्ताओं और सोलर कंपनियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्री पेड मीटर में रिचार्ज नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया जा रहा है। दोबारा रिचार्ज करने पर भी माइनस बैलेंस बताता है, ऐसे में उपभोक्ता अपने रिचार्ज को बढ़ाकर भी रख रहे है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है।राहिनी सोलर के सीईओ विकास मिश्रा ने कहा कि हर महीने इस समस्या को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। उन्हें समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। लेकिन आज तक इस समस्या का निदान नहीं निकल पाया।उन्होंने यह भी कहा अब उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का हल निकला जाएगा,इसके लिए विद्युत मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। समस्याओं का निराकरण न होने पर उपभोक्ताओं के साथ उच्चाधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

IAS रिंकू सिंह ने वापस लिया इस्तीफा

लखनऊ। यूपी काडर के वर्ष 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने राष्ट्रपति को भेजा अपना तकनीकी इस्तीफा वापस ले लिया है। काम नहीं तो वेतन नहीं और पूर्व में तैनात समाज कल्याण अधिकारी के पद पर वापस भेजने की शर्तों के साथ उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा था। अब बेहद गोपनीय तरीके से उनका इस्तीफा वापस हुआ है। इस मामले में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आईएएस रिंकू सिंह सिर्फ इतना कहते हैं कि मामला उच्च स्तर पर है, इसलिए वह इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। रिंकू सिंह ने 26 मार्च को राष्ट्रपति को तकनीकी इस्तीफा भेजा था। इसकी प्रति मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद के साथ प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को भी भेजी थी। उन्होंने इस पत्र में प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें काम करने का अवसर नहीं दिया गया और संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर एक अलग सिस्टम चल रहा है। वे वर्तमान में राजस्व परिषद से संबद्ध चल रहे हैं। उनका यह पत्र 30 मार्च को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं मीडिया से सामने आकर अपने इस्तीफे की बात कही थी। सूत्रों का कहना है कि अब उन्होंने अपना यह इस्तीफा वापस ले लिया है। उनका इस्तीफा वापस लिया जाना इतना गोपनीय रखा गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। नियुक्त विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका मामला उच्च स्तर पर है और इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में शाहजहांपुर की पुवायां तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद पर तैनाती के दौरान वकीलों के प्रदर्शन से जुड़ा उनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ था। इसमें वह कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद ही सरकार ने उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया था।

यूपी के सभी जिलों में सात दिन चलेगा श्रमिक स्वास्थ्य मेला, गंभीर रोगियों की होगी पहचान

लखनऊ। कामकाजी वर्ग स्वस्थ हो तो आर्थिक पहिया तेज घूमता है। प्रदेश सरकार श्रमिक दिवस पर एक मई को सभी जिलों में सप्ताहभर का स्वास्थ्य मेला आयोजित करेगी, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल से हो जाएगी। स्त्री रोग, बाल रोग एवं एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों की अलग क्लीनिक चलेगी। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने इस आशय का पत्र सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, प्रमुख चिकित्साधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र भेजकर मेले की तैयारी के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि श्रमिकों के बेहतर शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं कुशल कार्यसंस्कृति के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। इसी क्रम में विभाग लगातार स्वास्थ्य कैंप बढ़ा रहा है। इस बहाने टीबी के मरीजों की खोज भी हो आसान हो जाती है। अपर मुख्य सचिव के पत्र के मुताबिक श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में कैंपों की संख्या अधिक होगी। जिला प्रशासन, श्रम विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका होगी।

सभी 75 जिलों में 28 अप्रैल से चार मई तक चलने वाले श्रमिक स्वास्थ्य मेले में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर भी पूरा फोकस होगा। स्क्रीनिंग के दौरान वायरल बुखार, संक्रमण, कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी एवं सी के अलावा हाइपरटेंशन और मधुमेह के मरीजों को सूचीबद्ध कर गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में इलाज के लिए रेफर किया जाएगा।

सभी प्रकार की चिकित्सा जांचों का प्रबंध किया गया है। अगर किसी रिपोर्ट में कोई गंभीर लक्षण मिलता है तो मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से आनलाइन परामर्श लिया जाएगा। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पवन अरुण ने बताया कि श्रमिक स्वास्थ्य मेलों की विस्तृत गाइडलाइन सभी जिलों को भेजी गई है। तैयारियों की जा रही हैं। गंभीर मरीजों को रेफर किया जाएगा।

एनएसई ने किया सीईआरसी नियम 2026 में मार्केट कपलिंग लागू करने का स्वागत

● भारतीय पावर मार्केट में पारदर्शिता, कामकाज की दक्षता और एक समान कीमत तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

डी एस त्रिपाठी की रिपोर्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) द्वारा जारी पावर मार्केट (ड्राफ्ट सेकंड संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना का स्वागत किया है, जो मार्केट कपलिंग लागू करने से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ग्रिड इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) आयोग की मंजूरी से अगले 6 महीनों के भीतर पावर मार्केट कपलिंग प्रोसीजर (पीएमसीपी) तैयार करेगा, ताकि अलग-अलग पावर एक्सचेंजों में मार्केट कपलिंग को लागू किया जा सके। इस पर एनएसई ने कहा कि मार्केट कपलिंग की शुरुआत भारतीय पावर मार्केट में पारदर्शिता, कामकाज की दक्षता और एक समान कीमत तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस' के सिद्धांत के अनुसार, मार्केट कपलिंग लागू करना एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा सुधार है। बाजार से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे पावर मार्केट और मजबूत होगा तथा सही तरीके से कीमत तय करने में मदद मिलेगी। मार्केट कपलिंग लागू होने के बाद, मार्केट कपलिंग ऑपरेटर (ग्रिड इंडिया) सभी तीनों स्पॉट पावर एक्सचेंजों से बोली को एक साथ इकट्ठा करेगा और एक केंद्रीकृत सिस्टम के जरिए उनका मिलान करेगा, ताकि एक ही मार्केट-क्लियरिंग प्राइस तय की जा सके। इसके बाद सभी स्पॉट एक्सचेंज अपने-अपने ट्रेड इसी एक तय कीमत के आधार पर सेटल करेंगे। यह तरीका मूल रूप से एनएसई के मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के सेटलमेंट के तरीके से मिलता-जुलता है। इसमें किसी महीने की अंतिम सेटलमेंट प्राइस/ड्यू डेट रेट (डीडीआर) सभी तीन स्पॉट पावर एक्सचेंज (पीएक्सआईएल, आईईएक्स और एचपीएक्स) की रोज़ाना कीमतों के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज के आधार पर तय की जाती है। यह गणना डीएएम के सभी सेगमेंट (कन्वेंशनल, ग्रीन और हाई प्राइस) और हर दिन के 96 टाइम ब्लॉक्स को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके विपरीत, कुछ एक्सचेंज केवल रोज़ाना कीमतों का साधारण औसत लेते हैं, जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम को नजरअंदाज किया जाता है। एनएसई का डीडीआर तरीका वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, जिसमें असली ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर कीमतों को सही वेटेज दिया जाता है, जिससे ज्यादा सटीक और भरोसेमंद कीमत निकलती है। जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स शुरू होने के बाद से लेकर मार्च 2026 तक, पावर एक्सचेंजों में स्पॉट बिजली की कीमतों में लगभग 14% की कमी आई है, जिससे कुल मिलाकर सामाजिक लाभ बढ़ा है। हालांकि, अभी मार्केट कपलिंग लागू नहीं होने के कारण कीमतों में काफी अंतर बना हुआ है। एक तरफ वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (जिसका इस्तेमाल एनएसई करता है) और दूसरी तरफ साधारण औसत कीमत (जिसका इस्तेमाल कुछ अन्य एक्सचेंज करते हैं) के बीच बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। 20 अप्रैल 2026 तक, अप्रैल 2026 के लिए एनएसई का मंथली मूविंग एवरेज ड्यू डेट रेट (एमएवीजीडीडीआर) लगभग 3,802/एमडब्ल्यूएच है, जबकि साधारण औसत तरीके से निकाली गई कीमत लगभग 4,442/एमडब्ल्यूएच है। इस वजह से दोनों फाइनेंशियल एक्सचेंजों के बीच बिजली की कीमत में करीब 600-700 प्रति एमडब्ल्यूएच का अंतर पैदा हो गया है। अगर मान लें कि हर महीने लगभग 1,000 एमयू बिजली की खपत होती है, तो इस अंतर की वजह से डिस्कॉम्स को हर महीने करीब 70 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। साल भर में यह असर लगभग 840 करोड़ तक पहुंच जाता है। चूंकि स्पॉट मार्केट में इससे भी ज्यादा मात्रा में बिजली की खरीद-फरोख्त होती है, इसलिए कुल मिलाकर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव काफी बड़ा और गंभीर हो सकता है। इस विकास पर टिप्पणी करते हुए एमडी और सीईओ, एनएसई आशीष कुमार चौहान ने कहा, 'यह जो नया संशोधन किया गया है और इसके तहत मार्केट कपलिंग लागू की जा रही है, यह पावर मार्केट में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगर मार्केट कपलिंग को जल्दी लागू किया जाता है, तो सभी 3 स्पॉट एक्सचेंज और 2 फाइनेंशियल एक्सचेंज के लिए एक समान कीमत तय हो सकेगी। इससे कीमत तय करने की प्रक्रिया और बेहतर होगी, स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों पावर मार्केट मजबूत होंगे तथा पावर सेक्टर में ज्यादा निवेश आकर्षित होगा। '

पंजाब किंग्स के खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़

● पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई की मां का निधन हो गया है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आईपीएल 2026 के बीच पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वे आईपीएल खेलने के लिए भारत में हैं लेकिन इस बीच उनकी मां का निधन हो गया है। इसकी पुष्टि उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद नबी और करीम जनत ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। पंजाब आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उनकी टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और अंक तालिका में भी पहले स्थान पर मौजूद हैं। उमरजई की बात करें, तो उन्हें अब तक पीबीकेएस की तरफ से एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है।

अजमतुल्लाह उमरजई के साथी खिलाड़ियों ने जताया दुख

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों मोहम्मद नबी और करीम जनत ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की। उन्होंने उमरजई और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। करीम जनत ने लिखा, 'राष्ट्रीय खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई की मां के निधन से हम बहुत दुखी हैं। अल्लाह पाक मृत आत्मा को जन्नत नसीब करे और परिवार को सब्र दे। हम इन कठिन पलों में उनके साथ हैं। 'मोहम्मद नबी ने भी भावुक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि उमरजई की मां के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत के उच्च स्थान पर जगह दे और पूरे परिवार को धैर्य और ताकत प्रदान करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के नाम पत्र, लिखा- BJP CM का शपथ ग्रहण साथ मनाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को एक भावुक पत्र लिखा। यह पत्र उन्होंने विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के प्रचार समाप्त होने के अवसर पर लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य में अपने जनसंपर्क को आध्यात्मिक रूप से उत्साहवर्धक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, दोनों ही बताया। पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों' को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि हर चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र उत्सव होता है और उन्हें इसमें शामिल होकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस हुआ। अपने व्यापक चुनावी अभियान पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राज्य की जनता के सामने BJP का विकास का रोडमैप प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

सरकारी मदद के अभाव में खुद नाली की साफ-सफाई करने को मजबूर हुए ग्रामीण

● लंबे समय से ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी की तैनाती नहीं होने से गांव का सफाई व्यवस्था बदहाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लॉक प्रशासन की घोर संवेदनहीनता और लचर कार्यप्रणाली का खामियाजा आज ग्राम पंचायत सेवतरी के परसा टोले के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। शासन की ओर से गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर साल लाखों रुपये का बजट आवंटित किया जाता है और कागजों पर स्वच्छता अभियान के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये योजनाएं धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ रही हैं। सेवतरी ग्राम पंचायत में लंबे समय से सफाई कर्मचारी की तैनाती न होने के कारण गांव की नालियां गंदगी और कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं, जिससे गांव के हर कोने में संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण रुका हुआ गंदा पानी अब सड़ने लगा है। लेकिन ब्लॉक मुख्यालय इस गंभीर समस्या की ओर से पूरी तरह आंखें मूंदे बैठा है। अधिकारियों की इसी बेरुखी और प्रशासनिक उपेक्षा के बीच ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है, जिसका एक शर्मनाक उदाहरण सेवतरी के टोला परसा पर देखने को मिला, जहां नाली से आ रही सड़ांध और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से परेशान होकर एक व्यक्ति ने सरकारी तंत्र का इंतजार करने के बजाय स्वयं ही मोर्चा संभाल लिया। नाली में जमा भारी कीचड़ और मलबे के कारण पानी का निकास पूरी तरह बंद हो चुका था। जिसे देखते हुए मजबूरन उक्त व्यक्ति ने कड़ी धूप में घंटों श्रमदान करते हुए नाली में जमा कीचड़ को खुद ही साफ किया। यह दृश्य नौतनवा ब्लॉक प्रशासन के उन दावों की सरेआम पोल खोलता है जिनमें गांवों को स्वच्छ बनाने की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ एक आम नागरिक को अपनी बुनियादी सुविधा के लिए खुद नाली में उतरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि ब्लॉक मुख्यालय की उदासीनता के कारण पूरे ग्राम पंचायत में गंदगी का अंबार लगा है और बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद ने बताया कि सीघ्र ही सफाई कर्मचारी को भेजकर गांव की साफ-सफाई करवाई जाएगी।

शादी समारोह में मारपीट के बाद दूल्हे के भाई की मौत

● खुशी का माहौल मातम बदला

● मृतक की पहचान दूल्हे के भाई विनोद प्रजापति (32) के रूप में हुई

● स्टेज पर फोटो खिंचवाने को लेकर हुआ था विवाद

● मारपीट में तब्दील हुआ वैवाहिक कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज ब्यूरो। महाराजगंज जिले के अड्डा बाजार क्षेत्र में बीती रात रविवार को एक वैवाहिक समारोह मे मारपीट हो गया । मामला तूल पकड़ने के कारण कठोर हमला के वजह से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पहचान दूल्हे के ही भाई विनोद प्रजापति उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई । पूरा घटना स्टेज पर फोटो खिंचवाने को लेकर शुरू हुई और मारपीट होने लगा । जिसके बाद विवाद बढ़ने के कारण एक की जान चली गई के । जानकारी के अनुसार नौतनवा थाना क्षेत्र के चडलहा गांव से बारात सोनौली कोतवाली क्षेत्र के कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव आई थी। कार्यक्रम के दौरान वर और वधू पक्ष के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया .जिसमें कुल छह लोग घायल हो गए। घायलों में विनोद प्रजापति को गंभीर चोटें आई थीं।

उन्हें तत्काल गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया घटना से आक्रोशित परिजन शव को लेकर कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव पहुंचे। उन्होंने कन्या पक्ष के घर के सामने शव रखकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोनौली, नौतनवा और परसामलिक थानों की भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोनौली थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में दीनानाथ और शम्भू प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने यह भी बताया कि मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

स्वतंत्र प्रभात
जो लिखेगा, वही टिकेगा
ब्रेकिंग न्यूज़

ऋषिकेश आना शानदार अनुभव... एक्टर- सुनील शेट्टी

● 1500 महिलाओं को मिलेगा सहयोगफिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने चार धामयात्रा तैयारियों की जमकर प्रशंसा की है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ जानी-मानी हस्तियां भी इस आस्था की यात्रा में पूरे श्रद्धा भाव से शिरकत कर रही हैं. जाने माने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी भी इस दौरान ऋषिकेश पहुंचे. यहां आकर उन्होंने पुलिस प्रशासन की तैयारियों को सराहा है. उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। फिल्म कलाकार सुनील शेट्टी ने अपनी यात्रा को शानदार अनुभव बताया है. उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर फैलाई जा रही नकारात्मक बातों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु ऐसी बातों पर न ध्यान दें। सुनील शेट्टी ने कहा कि आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि यात्रा के दौरान ट्रैफिक और भीड़ से लोग परेशान रहते हैं,

या फिर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होतीं, लेकिन उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा। यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लगा।

पुलिस 24 घंटे व्यवस्था दुरुस्त बनाने में लगी है-सुनील

ऋषिकेश पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि यहीं से चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है. यहां देशभर से हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं, इसके बावजूद ऋषिकेश में यातायात सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस 24 घंटे परिश्रम करते हुए व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. सुनील शेट्टी ने इसके लिए उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सराहना की है. अभिनेता ने कहा कि वो अगले दौरे पर चारधाम दर्शन के लिए भी जाएंगे. उनके इस बयान से साफ है कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चल रही है।

डॉ. प्रीति अदाणी का स्वाभिमान विज़न मध्य प्रदेश पहुंचा

● 1500 महिलाओं को मिलेगा सहयोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

डी एस त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। बदरवास, मध्य प्रदेश (एमपी) में अब स्थायी आय की तलाश कर रही महिलाओं को कमाई और आत्मनिर्भर बनने की नई राह मिलेगी। इसी दिशा में, अदाणी समूह की सामाजिक सेवा और विकास इकाई, अदाणी फाउंडेशन ने शिवपुरी जिले के बदरवास में अदाणी विकास केंद्र शुरू किया है, जिससे महिलाओं के लिए घर के पास ही व्यवस्थित रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अदाणी फाउंडेशन के स्वाभिमान कार्यक्रम का अखिल भारत में 10 लाख महिलाओं को सतत आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य है। इसका फोकस महिलाओं को असंगठित और अनियमित काम से निकालकर बाजार से जुड़े स्थायी आय के अवसरों तक पहुँचाने पर है। करीब 48,000 वर्ग फुट में फैला यह केंद्र अपनी पूरी क्षमता पर 600 आधुनिक सिलाई मशीनों के साथ काम करेगा और इसे ट्रेनिंग और प्रोडक्शन दोनों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ महिलाओं को व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएँगे और नियमित रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे-जैसे यह केंद्र अपना विस्तार करेगा, लगभग 1,500 महिलाओं को स्थायी आय मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपने परिवारों को अधिक आत्मविश्वास के साथ सहयोग कर सकेंगी। इस केंद्र का उद्घाटन संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) के केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस कार्यक्रम में आसपास के गाँवों की 5,000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो स्थानीय भागीदारी और आजीविका के अवसरों की मजबूत माँग को दर्शाता है।

इस मौके पर श्री सिंधिया ने कहा, 'बदरवास में जो हम देख रहे हैं, वह सपनों को साकार होते देखने की ताकत है। मैं अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच बनाया है, जहाँ कौशल वैश्विक बाजारों तक पहुँच सकता है। मेरी प्यारी दीदियों की आखों में उनका संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी उम्मीदें और सपने अब सार्थक आजीविका के जरिए साकार हो रहे हैं। यह केंद्र सशक्तिकरण का एक सच्चा इंजन है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले पाँच वर्षों में बदरवास के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएँगे। ' अदाणी फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अभिषेक लख्ताकिया ने कहा, 'हमारी चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी के इस विश्वास से प्रेरित होकर कि महिलाओं का सशक्तिकरण सम्मानजनक आय से शुरू होता है, स्वाभिमान कार्यक्रम कौशल को स्थायी आय में बदलने पर काम करता है। महिलाओं को वास्तविक काम और बाजार से जोड़कर हम उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और परिवार व समाज में मजबूत भूमिका निभाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। ' बदरवास में इस पहल से परिवारों की आय बढ़ने, अनौपचारिक काम पर निर्भरता घटने और पलायन की जरूरत कम होने की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कौशल और बाजार तक पहुँच में निवेश करके अदाणी फाउंडेशन यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाएँ नियमित आय कमा सकें और अपने तथा अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकें। अदाणी फाउंडेशन इस वर्ष 11 अगस्त को अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो भारत के कोने-कोने में समावेशी विकास के प्रति तीन दशकों की लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अदाणी फाउंडेशन के बारे में जानकारी सन् 1996 से अदाणी फाउंडेशन, अदाणी ग्रुप की सामाजिक कल्याण और विकास इकाई के रूप में, अखिल भारत में स्थायी परिणामों के लिए रणनीतिक सामाजिक निवेश करता आ रहा है और लगातार सक्रिय व प्रतिबद्ध रहा है।

यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्थायी आजीविका, जलवायु कार्रवाई और सामुदायिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के जीवन को सशक्त और समृद्ध बना रहा है। फाउंडेशन की रणनीतियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में अदाणी फाउंडेशन 22 राज्यों के 7,247 गाँवों और शहरी वार्ड्स में काम कर रहा है और 1.33 करोड़ लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

दिल्ली में मई से सितंबर तक 5 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

● आबकारी विभाग ने जारी की 'ड्राई डे' की लिस्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में आने वाले समय में पांच दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर दिल्ली के आबकारी विभाग द्वारा आदेश के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी शामिल हैं। बुद्ध पूर्णिमा के चलते 1 मई, ईद-उल-जुहा के चलते 27 मई, मुहर्रम के दिन 26 जून, स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त और और जन्माष्टमी पर 9 सितंबर को शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सभी लाइसेंस होल्डर अपनी दुकान में किसी खास जगह पर शराब बंदी की जानकारी निर्धारित दिन से पूर्व बताएंगी। आदेश में कहा गया है कि एल-15 और एल 15 एफ लाइसेंस वाले होटलों के मामले में इन

दिनों पर शराब की बिक्री रुके हुए निवासियों को शराब की सर्विस पर लागू नहीं होगी।

डीटीसी बसों में ठंडा पानी, मजदूरों को दोपहर में आराम; हीट वेव पर दिल्ली सरकार का सख्त आदेश

नई दिल्ली। बढ़ रहे तापमान व लू से लोगों विशेषकर श्रमिकों, स्कूली बच्चों और धूप में यात्रा करने वालों को परेशानी हो रही है। इनकी परेशानी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों व निजी एजेंसियों को हीट वेव एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की सभी बसों में कोल्ड बाक्स में ठंडा पानी रखने को कहा गया है। बस शेल्टरों के पास भी पानी के काउंटर लगाए जाएंगे, जहां निश्शुल्क ठंडा पानी और ओआरएस के घोल मिलेंगे।

श्रमिकों को दिया जाएगा आराम

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को धूप में काम नहीं करना पड़े। सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि दोपहर एक बजे से शाम चार बजे के बीच श्रमिकों को आराम दिया जाए। उनके लिए पानी, आराम करने के लिए छायादार स्थान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी। स्कूलों में गर्मी से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने और छुट्टी से पहले बच्चों को ओआरएस का घोल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को भी सफाई कर्मियों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और धूप में काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं।